

पूरी दुनिया समझ रही है सनातन संस्कृति को: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

**हर ब्लॉक में वृद्धावन गांव बनाए जाएंगे, दुम[ा]
उत्पादन में प्रदेश को नंबर वन बनाएंगे**



भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को अब बेहतर तरीके से समझ रही है। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में एक वृद्धावन गांव बनाया जाएगा और दुध उत्पादन में प्रदेश को देश में नंबर वन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंदसौर में सोमयज्ञ में सम्मिलित हुए और यज्ञ में आहुति देने के साथ संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूजा-अर्चना की तथा सुख, शांति, समृद्धि कामना की। मुख्यमंत्री ने मंच से संत जनों का शॉल-श्रीफल से सम्मान किया। पवित्र नगरी मंदसौर को नशा मुक्त करने पर 160 समाजों द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मुख्यमंत्री डॉ. यादव न कहा था। आज हम सब सोमयज्ञ का हिस्सा बने हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस यज्ञ का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को समझ रही है। सनातन संस्कृति की अपनी अलग विशेषता रही है। दुर्घट उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान

पर ह। प्रदेश में वतमान में ९७ दूध उत्पादन होता है जिसको बढ़कर 20 प्रतिशत किया जाएगा। दूध उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर ब्लॉक में वृद्धावन गांव बनाए जाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जाएंगे। गांव की गौशाला अच्छे से संचालित हो इसके लिए प्रयास होंगे। एक व्यक्ति 25 गाय की एक इकाई मानकर आठ इकाई रख सकते हैं। कामधेनु योजना को जमीन स्तर पर उतारेंगे। समाज में संस्कार दिखे इसके लिए धार्मिक नगरों में शराबबंदी की गई। कृष्ण की लीलाओं के पवित्र स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगे।

मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन ऐतिहासिक पहल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित और इस क्षेत्र में यहां अपार संभव है। किसानों की आय, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन में वृसाथ-साथ खाद्य प्र-संस्करण और से उत्पादित कच्चे माल पर 3 औद्योगिक इकाई स्थापित करने संभव प्रयास जारी हैं। किसानों गौपालकों की आय बढ़ाने के साथ कृषिएषण दूर करने की योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य में दुग्ध बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ की जा रही हैं। मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन 9 प्रतिशत से जल्द से जल्द 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. अम्बेडकर कामधेनु योजना प्रारंभिक किया है। इससे हम घर-घर गोकुल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कहा कि हमने गौशालाओं में पशुओं के लिए भी अनुदान राशि का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री यादव ने बुधवार को मीडिया के संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की विकसित भारत अंतर्राष्ट्रीय विजन के अनुरूप हमारी सरकार गरीब, युवा, अननदाता (किसान नारी कल्याण के लिए मिशन शुरू) दिए हैं। मंत्रि-परिषद की गत मंगलवार को बैठक में मध्यप्रदेश कल्याण मिशन को सैद्धांतिक संदर्भ दे दी गई है।

बांधवगढ़ की 200 एकड़ वनभूमि पर अवैध

भोपा

एमपी के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ में करीब 200 एकड़ वनभूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। कब्जाधारियों ने इस जमीन पर खेती और मकान बना लिए हैं। यह जमीन वनसंरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस मुद्दे का लेकर खलौंद निवासी रामलखण्ड सेन ने एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत द जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने इस पर गंभीरता दिखाई है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई वे बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव व विभाग, उमरिया कलेक्टर, व अधिकारी व डिप्टी डायरेक्टर को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह वे भीतर जवाब प्रस्तुत करने वे निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता वे

An aerial photograph showing a cluster of destroyed buildings, likely from a conflict. The buildings are multi-story structures with multiple windows, many of which are broken or missing. The ground around the buildings is dirt and debris. A few small trees are scattered in the surrounding area. The overall scene is one of desolation and destruction.

अधिकारी भी संपत्ति के मामले में पीछे नहीं हैं। खास बात यह है कि इन अफसरों ने देश के बड़े शहरों के अलावा उन क्षेत्रों में भी संपत्ति खरीदी है जो टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित हैं। इन अफसरों ने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी में बताया है कि उन्होंने देश और प्रदेश के बड़े शहरों जैसे इंदौर, सिवनी, छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा, महेश्वर में भी जमीन, मकान और प्लॉट खरीदे हैं। खास बात यह है कि इन जिलों के जिन इलाकों में जमीन खरीदी गई हैं, वह टाइगर रिजर्व के आसपास आते हैं।

18-19 अप्रैल को अवकाश के दिन में भी सभी उपार्जन केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीदी

भोपाल। प्रदेश के अन्नदाताओं की सुविधा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी उपार्जन केन्द्रों पर आगामी 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक कर बिना किसी परेशानी के गेहूं विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने समस्त जितांतों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में उपार्जन केन्द्रों की निरंतर मॉनीटरिंग करें।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी विंध्य की माटी का गौरवः उप मुख्यमंत्री शुक्ल



थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी
का भोपाल स्थित निवास पर किया
आत्मीय स्वागत

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने 3 अप्रैल भोपाल स्थित निज निवास पर भारत थलसेना अध्यक्ष जनरल उपरेंद्र द्विवेदी एवं उन धर्मपत्री का सपरिवार आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि विन्ध्य अंचल की धरती से निकलकर भारत सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचे जनरल उ

द्विवेदी 'विध्य की माटी का गौरव' हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जनरल उपर्योग द्विवेदी को देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता एवं अनुकरणीय सेवाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि जनरल द्विवेदी विध्य क्षेत्र के उन अनमोल रत्नों में से हैं, जिन पर सम्पूर्ण प्रदेश को गर्व है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि जनरल द्विवेदी जैसे व्यक्तित्वों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शुक्ल एवं जनरल द्विवेदी के मध्य विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक एवं उपयोगी चर्चा हुई।

**ताप विद्युत गृहों में बायोमास के उपयोग के
लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा**

भोपाल। प्रदेश में पराली जलाने से होने वाले बायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये उपलब्ध बायोमास के ताप विद्युत गृहों में उपयोग के संबंध में बुधवार को प्रदेश के सभी 15 ताप विद्युत गृहों एवं 17 कैप्टिव ताप विद्युत गृहों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री नवनीत मोहन कोटारी के साथ प्रदेश के सभी ताप विद्युत गृहों एवं कैप्टिव ताप विद्युत गृहों के अधिकारी वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री कोटारी ने बताया कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल कोयला खपत का 5 प्रतिशत तथा वर्ष 2025-26 में कुल कोयला खपत का 7 प्रतिशत बायोमास कोयले के साथ बॉयलर में जलाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार प्रदेश के सभी ताप विद्युत गृह निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं हैं। ताप विद्युत गृहों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बायोमास के उपयोग के लिये समुचित कार्रवाई की जा रही है। इसमें बायोमास के फीडिंग सिस्टम, लोडिंग-अनलोडिंग, भंडारण संबंधी व्यवस्थाओं का विकास बायोमास प्रदाय करने के लिये उपलब्ध वेण्डर्स की इन्वेन्ट्री एवं टेंडर संबंधी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ ताप विद्युत गृहों जैसे जयप्रकाश पॉवर वेन्चरर्स सिंगरौली एवं बीना, हिंडाल्कौ सिंगरौली, एनटीपीसी लिमिटेड के विंध्याचल, गाडरवारा और खरगान में बायोमास का उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है। इसे लक्ष्य अनुसार किया जायेगा। प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि प्रदेश में बायोमास निर्धारित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसीलिये प्रदेश के बाहर जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बायोमास को वेण्डर्स के माध्यम से प्राप्त कर उसका उपयोग कर रहे हैं। शासन द्वारा भी प्रदेश में बायोमास आधारित पैलेट/ब्रिकेट मैन्युफ्करिंग उद्योगों की स्थापना का प्रयास किये जाने चाहिये।

श्रमदान कर जल संरचनाओं के संरक्षण और सफाई के लिए किए जा रहे काम



में जल के महत्व पर भाषण प्रतियोगिता हुई। छात्राओं ने जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अपने विचार रखे। छात्राओं ने कहा कि जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देना होगा। धार जिले में नगर के रामतलाई तालाब की साफ-सफाई का कार्य किया गया। इस कार्य में जिला आयुष कार्यालय से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने तालाब की सफाई का कार्य किया। अंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 80 त्रिमूर्ति नगर की कार्यकर्ता और सहायिका ने आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सकों से पोषण आहार के बारे में जानकारी प्राप्त की। तालाब के सफाई कार्य में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। बड़वानी जिले में जन

**राज्य आनंद संस्थान खुशहाली
आत्म-संतोष और सामूहिक सङ्ग्राव
बढ़ाने के लिए प्रयासरत**

भापाल। राज्य आनंद संस्थान जीवन में खुशहाला, आत्म-सततपूर्वक और सामूहिक सद्बाव को बढ़ावा देने के लिए सतत कार्यरत है। आनंद शिविरों के माध्यम से इस दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। आनंद शिविर का आयोजन शासकीय एवं अशासकीय आनंदकों के लिए किया जाता है। इन शिविरों का उद्देश्य प्रतिभागियों को परिपूर्ण जीवन जीने की विधा सिखाना एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आनंद संस्थान आशीष कुमार ने बताया कि जीवन में आनंद के साथ प्रत्येक कार्य करना चाहिए। विभाग का उद्देश्य आनंद एवं सकुशलता को मापने के पैमानों की पहचान तथा उन्हें परिभाषित करना है। राज्य में आनंद का प्रसार करने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिये दिशा-निर्देश तय करने का कार्य भी किया जा रहा है। आनंद की अवधारणा का नियोजन नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाना, आनंद की अनुभूति के लिये एकशन प्लॉन एवं गतिविधियों का निर्धारण भी किया जा रहा है। निरंतर अंतर्राष्ट्रीय पर निर्धारित मापदण्डों पर राज्य के नागरिकों की मनःस्थिति का आंकलन करना, आनंद की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना, आनंद के प्रसार माध्यमों, उनके आंकलन के मापदण्डों में सुधार के लिये लगातार अनुसंधान करना और आनंद के विषय पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने का कार्य आनंद विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कटनी में विकासखंड ढीरमखेड़ा के प्रधानाध्यापकों के लिए नेतृत्व क्षमता विकास पर पांच दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

संपादकीय

उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख

३ तर प्रदश सरकार पछल कुछ वर्षों से कानून का शासन स्थापित करने के दावे खूब

बढ़-चढ़ कर करती रही है। मगर जमीन पर वे दावे खोखले ही निकलते रहे हैं! अपराध के खिलाफ उसकी कार्रवाई की वास्तविकता यह भी है कि नियम-कायदों के उल्लंघन की प्रकृति होती कुछ और है, लेकिन उसे कानूनी दस्तावेजों में किसी और रूप में दर्ज किया जाता है। ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस रवैये के खिलाफ सख्त रुख अखित्यार किया, जिसमें दीवानी विवादों को फौजदारी मामलों में बदला जा रहा है। अदालत की पीठ ने इसे ‘कानून के शासन का पूरी तरह पतन’ करार देते हुए कहा कि यह प्रथा गलत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। अदालत की यह टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आए दिन कानून का शासन लागू करने को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, उस पर वास्तव में अमल करने के मामले में पुलिस किस तरह मनमानी करती है और विवादों को कैसा रूप दिया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून-व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली ऐसी मनमानी के बूते क्या किया जा रहा है और क्या दर्शाया जा रहा है। केवल पैसा न लौटाने को क्या ऐसे कानूनी दायरे में रखा जा सकता है, जिसे अपराध घोषित कर दिया जाए और उसी मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए? अदालत ने इस पर तल्ख रुख अखित्यार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज दीवानी मामलों को फौजदारी के मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है, सिर्फ लंबा वक्त लगने की दलील देकर दीवानी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी और आपराधिक कानून लगा दिया जाएगा। सवाल है कि क्या इसी तरह का रवैया अपना कर राज्य सरकार अपराधों पर काबू पाने का दावा कर रही है। अगर खुद पुलिस महकमे और उसके अधिकारी नियमों को इस तरह ताक पर रख रहे हैं, तो आपराधिक मामलों में उनकी कार्रवाईयों को कितना विश्वसनीय माना जाएगा?

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि नहीं चेते तो अंजाम और भी बुरे होंगे!

-कमलेश पां

बवक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि हमारा प्रशासन समय रहते ही नहीं चेता तो आने वाले दिनों में अंजाम और भी बुरे होंगे, इतिहास इसी बात की चुगली कर रहा है! यह नसीहत कर्त्तर वक्त हमें बार-बार दे रहा है, लेकिन हमलोग ऐसे घिसे पिटे आदर्शवादी हैं कि उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इसलिए आज मैं इतिहास की अंगाड़ी में सुलगते हुए वर्तमान के कुछ कटु सत्य को उद्घाटित कर रहा हूँ ताकि हमारे राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की कुम्भकर्णी निंदा टूटे और वो विधि-व्यवस्था के लिहाज से अपने मौलिक कर्तव्य न भूलें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत एक शार्तप्रिय देश रहा है, लेकिन पहले मुस्लिम आक्रान्ताओं ने और फिर ब्रिटिश नौकरशाहों ने अपने अपने प्रशासनिक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी-ऐसी अव्यवहारिक नीतियों को कानूनी अमली जामा पहनाया, जिससे हिन्दू समाज जाति और क्षेत्र के नाम पर बिखर गया और कभी मुस्लिम अधिकारी तो कभी ईर्झा अधिकारी और उनके पिछू लोग हिन्दुओं पर हावी होते चले गए। इसी कड़ी में सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय हिंसा को अधोपिष्ठ प्रशासनिक एजेंडे के तौर पर बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा, कभी प्रशासनिक

उदासीनता तो कभी पक्षपाती दृष्टिकोण
अपनाते हुए संगठित अपराध को बढ़ावा
दिया गया, जिससे विधि व्यवस्था की
स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली गई।
इसी स्थिति से निजात पाने के लिए देश
में आजादी की लड़ाई तेज हुई और
साम्प्रदायिक विभाजन तक की नौबत
आई। इस दौरान हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी
खूब हुए। लेकिन भारत के गाँधी-नेहरू
जैसे अव्यवहारिक आर्द्धशावादी
राजनेताओं ने आजाद भारत में हालत
बदलने के उलट उर्ही घिसे-पिटे कानूनों
को भारतीयों पर थोप दिया, जो आज
तक अशांति का सबब बन चुकी हैं।
पहले कांग्रेसियों, फिर समाजवादियों
और अब राष्ट्रवादियों ने ढोंगी
धर्मनिरपेक्षता की तो खूब बातें कीं,
लेकिन अपने कुत्सित जातीय, क्षेत्रीय
और सांप्रदायिक एंजेंडे से आगे की कभी
नहीं सोच पाए। मसलन, बहुमत की आड़
में शांतिप्रिय सत्ता परिवर्तन भी सुनिश्चित

हुआ, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका और समाजपालिका से जुड़े लोग मुश्लिया और ब्रिटानी प्रशासनिक लापरवाहियों से कोई सबक नहीं सीख पाए। सबों ने उस 'निर्जीव भारतीय संविधान' का महिमा मंडन किया और कर रहे हैं जिसने पदासीन लोगों को बेतन-भत्ते-पैंशन और देशवासियों से लूट-खसोट की तो गारंटी दी, लेकिन आमलोगों के सुख-शांति में खलल डालने वालों के खिलाफ कभी सख्ती नहीं दिखाई। इस नजरिए से संसद और विधान मंडलों ने प्रभावकारी कानून नहीं बनाए और न ही न्यायपालिका ने इस प्रशासनिक प्रवृत्ति पर कभी सवाल उठाए। हद तो यह कि न्याय के नाम पर मामलों को वर्षों तक लटकाने वाली न्यायपालिका, नेताओं के इशारों पर उलटे-सीधे कार्य करने की अभ्यस्त हो चली कार्यपालिका और नेताओं-कारोबारियों की अघोषित

सांठागाठ से जहा सत्ताधारा जमात मोज में रहता आया है, वहीं आम आदमी सुपोषण योग्य भोजन, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा, जन-सुरक्षा के लिए मोहताज है। एक ओर देश के अमनपसंद आमलोग जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्पादन की प्राप्ति के लिए आरक्षण को अचूक हथियार समझ बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर 1947 में पाकिस्तान और 1972 में बंगलादेश लेने वालों के बंशज ब्रेक के बाद भारतीय भूभाग पर सांप्रदायिक तांडव मचा रहे हैं और नेताओं की नीतिगत लापरवाहियों से हमारा सिविल और पुलिस प्रशासन असहाय बना रहता है। हैरत की बात है कि कभी ये लोग दलित-मुस्लिम समीकरण तैयार करवाते हैं तो कभी मुस्लिम-ओबीसी समीकरण को फिंडिंग करवाते हैं। वहीं इसी की आड़ में अभिजात्य मुसलमान विदेशों से हवाला के जरिए फिंडिंग लेकर देश में पाकिस्तान-बंगलादेश के ही नहीं बल्कि अब देशों के हमदर्द पैदा करते हैं। इनकी नापाक मंशा जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे हालत पूरे देश में पैदा करने की है, जिसकी झलक गाहे-बगाहे दिखाते रहते हैं। यदि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक के ब्रेक के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों की बात छोड़ भी दी जाए तो अयोध्या रामजन्म भूमि आंदोलन, फिर सीएए और अब बक्सफ कानून की आड़ में पाकिस्तानी खुण्डिया एजसीआई के इशारे पर या फिर चीन-अमेरिका-इंग्लैंड से शह प्राप्त अन्य मुस्लिम देशों के इशारे पर भारत में जो अशांति फैलते हैं, इसका ताजातरीन उदाहरण पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका है, जो इन दिनों इस्लामिक उत्पात से जल रहा है। दरअसल बक्सफ कानून में संशोधन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़क उठी है, उससे केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाओं की आशंका जताई है। इसके दृष्टिगत वह लगातार सतर्कता बरत रही है। यह बात दीगर है कि अभी तक अन्य राज्यों से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक, बक्सफ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की अधिसूचना के मद्देनजर अभी तक अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी सांप्रदायिक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई जोखिम नहीं उठा रहा है। केंद्र बंगाल के साथ-साथ अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जहाँ बक्सफ कानून विरोधी प्रदर्शनों की खबरें आई हैं। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी कारक की पहचान करना और संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए।

जीवन धारा: मुरकुराहट ऊपरी न हो,
भीतर से आए, करुणा रखना अहम सूत्र

-श्री श्री रविशंकर

समुद्र के किनार कुछ लोग शाम के
ऐसे ही टहलने के लिए जाते हैं। वे सिफर
टहलने भर से खुश होते हैं। ताजी हवा
मिल जाती है। कुछ लोग अपने जूते बगैर
उतारकर ठंडे पानी में पैर रखते हैं और
उसी से खुश हो जाते हैं। किंतु कुछ लोगों
इससे भी तुस नहीं होते और पानी में तैरने
के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं
कुछ लोग समुद्र की गहराई में डुबकी
लगाकर उसमें से कुछ रस, मूंगा, मोता
निकालने जाते हैं, तो कुछ लोग मछलियाँ
पकड़ने के लिए जाते हैं। और कुछ लोग
उसके पानी से नमक बनाकर खुश होते
हैं, तो कुछ समुद्र से तेल निकालते हैं।



सागर के पास जाते हैं, उनसे नहीं कहता,
 'अरे, गहराई में ढुबकी लगाओ, वहां मोती
 है, मुँगा है, वह सब निकालो।'

जिसे जो चाहिए, वह उसमें से स्वयं
ले लेगा है। ज्ञान का भी ऐसा ही सागर है।

यह नहा कहता, 'भाई, यहां तल पड़ा ह, तल ले जाओ।' और जो तल के लिए ल लता ह। ज्ञान का भा एसा हा सागर ह, इसमें हम जितनी गहराई में उत्तरते हैं, उतने

ही हम सुखी होते हैं। तो आप स्वयं से पूछो, आपको क्या चाहिए? आप प्रश्न पूछो और निकाल लो जवाब। मुझसे पूछा गया कि सफल जीवन किसे कहते हैं? हम खश हो सकें। दिल खोलकर बात कर

चमक हो। मुस्कराहट ऊपर की न ही भीतर से आए। ऊपर से? तो हम अवश्य मुस्कराते हैं, कोई शर्त भी आ जाए, तो भी मुस्कराकर पूछते हैं, ‘हाँ भाई, कैसा हो?’ किंतु भीतर से बुरा-भला कहते हैं, यह तो ऊपर से नाटक करना हो गया।

हममें एक आंतरिक मस्ती होनी चाहिए।
हरदम मस्त रहना चाहिए।
वही सफल जीवन है, जिसमें हमारी

हंसी ऐसी मजबूत हो कि कोई भी हमसे उसे छीन न पाए। अक्सर छोटी-मोटी बातों से हमारी हंसी उड़ जाती है। ऐसा होता है न? मान लीजिए, आप बहुत खुश हैं और टेलीफोन पर किसी ने कुछ कठोर शब्द कह दिए। बस, झट से आपका माथा गर्म हो जाता है। यह आप सबका अनुभव है कि नहीं? जीवन में सफलता को तभी नाप सकते हैं, जब हमारी हंसी हर अवस्था में एक-सी बनी रहे। देखिए, आप जीवन-भर खुशी की तैयारी में लग जाते हैं।

मान लो, आप अस्सी साल के हैं, तो
चालीस साल तो आपने सोकर निकाल
दिए, बीस-पच्चीस साल काम करने में
निकाल दिए, बाकी के पंद्रह-बीस साल
नहाने-धोने में, खाने-पीने में, यात्रा में
निकाल दिए। हाँ, बचपन के दो-तीन साल
मस्ती से गुजारे। या साल में दो-चार दिन,
जब कोई त्योहार आया, या कुछ और
उत्सव हुआ, तो हँसी में समय बिताया।
इसके सिवाय बाकी सब समय तो जीने
की तैयारी में ही निकल गया।

मोदी का नया मंत्रः देरी विकास का दुश्मन

-उमेश चतुर्वेदी

अमेरिकी लेखक जय एम फिनमैन की अमेरिकी बीमा कंपनियों के कामकाज को लेकर कुछ साल पहले एक पुस्तक आई थी, डिले, डिनाय, डिफेंड... अंग्रेजी के इन तीन शब्दों का अर्थ है टालना, इनकार करना और बचाव करना। इस पुस्तक में फिनमैन ने साबित किया है कि किस तरह बीमा कंपनियां दावों को टालती हैं, देने से इनकार करती हैं और फिर अपने फैसले का बचाव करती हैं। नौकरशाही से जिनका पल्ला पड़ता रहता है, उन्हें भी पता है कि नौकरशाही किस तरह फैसलों को टालती हैं, उनके हिसाब से योजना नहीं हुई तो उससे आगे बढ़ाने से इनकार कर देती है और आखिर में उस योजना का पलीता ही लगा देती है। इस देर और इनकार की कीमत आखिरकार जनता को चुकानी पड़ती है। अब्बल तो तय समय पर लोगों को सहूलियतें मिल ही नहीं पाती। लेकिन जब किसी वजह से परियोजना पर काम चलता भी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी लागत खर्च बढ़ चुकी होती है। आखिरकार इसकी कीमत देश को ही चुकानी पड़ती है।

लंबे समय तक गुजरात के

A portrait of Prime Minister Narendra Modi. He is wearing a bright orange turban and a white kurta-pajama. He is standing behind a dark wooden podium with two microphones attached by black cables. The background is a textured blue wall.

योजना पर दोबारा काम मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ और चार साल में यह पुल बनकर तैयार हुआ और 2018 इसे जनता के लिए खोला गया। अगर इसी हिसाब से देखें तो यह काम 2001 या अधिक से अधिक 2002 में पूरा किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

सत्ताएं बदलते ही कई योजनाएं रोक दी जाती हैं और राजनीतिक नफा-नुकसान को देखते हुए उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। केरल की कोल्लम बाईपास सड़क परियोजना को इसके उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। यह योजना 1972 में शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हुई। तकरीबन

पचास साल तक यह योजना लटक रही। यह बात और है कि इस काम के मोदी सरकार ने ही पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या देश के सामने कोई लक्ष्य खोते हैं, तो वे नया नारा भी गढ़ते हैं। 'देरी विकास का दुश्मन है' इकड़ी में नया नारा है। देश में ऐसी काम परियोजनाएं मिल जाएंगी, जिन्हें तब वक्त तक पूरा नहीं किया जा सकता। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए धाघरा नदी पर माझी में एक पुल है। प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने इस पुल को केंद्र में रखकर कविता ही रच डाली है। इस पुल के शिलान्यास जनता पाटी के शासनकाल

के राज्य मंत्री चांद राम ने शुरू किया और दशकों तक इसका काम नहीं हो पाया। अरसे बाद यह पुल बनकर तैयार हो पाया। परियोजनाओं में देरी की ऐसी ढेरों कहानियां पूरे देश में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना का भी इसी संदर्भ में उल्लेख किया है। देश की आर्थिक राजधानी के लिए बेहतर और सुगम हवाई सेवा की जरूरत से किसे इनकार हो सकता है। लेकिन नवी मुंबई में हवाई अड्डा बनाने की चर्चा साल 1997 में शुरू हुई। लेकिन उस परियोजना को ठीक दस साल बाद यानी 2007 में मंजूरी मिल पाई। लेकिन राजनीति और नौकरशाही से कोलाज बाले तंत्र की वजह से इस परियोजना पर ठोस रूप में काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने तो सीधे-सीधे इसके लिए इस दौरान केंद्र और महाराष्ट्र में काबिज रही कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री के अनुसार, कांग्रेस की सरकारों ने इस परियोजना में ना तो दिलचस्पी दिखाई, ना ही कोई कार्रवाई नहीं की। यह बात और है कि मोदी सरकार ने इस परियोजना के कामकाज में तेजी लाने की दिशा आगे बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह दूसरी योजनाएं तेज गति से तय वक्त या उससे बहले पूरी हुईं, उसी गति और तेजी से नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना भी पूरा होगी। देश के आर्थिक विकास की नींव नरसिंह राव ने साल 1991 में रखी थी, जिनके सहयोग से तत्कालीन वित्त मंत्री मनोहार सिंह ने उदारीकरण की गति को तेज किया था। देश की आर्थिकी को लाइसेंस राज और लालफीताशाही से दूर किया था। उस बदलाव का असर भी दिखा। लेकिन राजकाज की कमान जिस तंत्र के हाथों में रही, वह पुरानी मानसिकता से ग्रस्त रहा। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद इस मानसिकता को थोड़ी लगाम जरूर लगी है। यह बात और है कि इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 'देरी, विकास का दुश्मन है' के प्रधानमंत्री के नए मंत्र का ही असर कहा जाएगा कि आर्थिक मोर्चे पर तय लक्ष्यों को हासिल करना आसान हुआ। आर्थिक मोर्चे पर बदलाव का ही असर है कि कुछ ही वर्षों में दुनिया की 11वें नंबर से भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनिया भर की विकास दर को कोरोना की महायारी ने बुरी तरह प्रभावित किया। आज की दुनिया के विकास का ईंधन एक तरह से जैविक ऊर्जा यानी पेट्रोल और डीजल है।

सावधान किसान! भूलकर न करें ये गलती, वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता

नालालाल किसान



प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार चलाती है। अगर आप भी एक पात्र किसान हैं तो आप इस योजना से जुड़कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं। इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। अब तक 19 किस्त जारी होने के बाद अब बारी 20वीं किस्त

की है, लेकिन उससे पहले किसान ये जरूर जान लें कि आपकी एक छोटी सी गलती या भूल के कारण आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। जालसाज किसानों को ठगने के लिए कई तरीके अपना रखे हैं, इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप फॉड से बच सकें। आप भी पीछे किसान योजना के लाभार्थी हैं

तो ई-केवाईसी के नाम पर होने वाले फॉड से बचकर रहें वयोंकि जालसाज किसानों को ठगने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। इसमें आपके पास कॉल आ सकता है जिसमें ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाने के लिए तीन तरीके हैं जो आपकी किस्तों में दिया जाता है। साथ ही आपको डाया भी जा सकता है कि अगर आप अभी हमसे ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपकी किस्त

अटक सकती। ऐसे में आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है और न ही ऐसी कॉल पर आपनी कोई भी गोपनीय जानकारी जैसे, बैंक खाते की डिटेल्स या योजना का राजिस्ट्रेशन नंबर, ऑटोपी जैसी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। जान लें कि ई-केवाईसी करवाने के सिर्फ तीन तरीके हैं जो आधिकारिक रूप से विभाग द्वारा बताए गए हैं।

शादी होने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन सकता?



शादी किसी भी धर्म की हो उसे हमेशा पवित्र ही माना जाता है। दो लोग एक साथ आकर जिंदगी भर साथ रहने का फैसला करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शादी दो लोगों में नहीं बल्कि, दो परिवारों में होती है।

यही नहीं, लोग अपनी शादी की रजिस्टर्ड भी करते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी कानूनी रूप से शादी रजिस्टर हो सके ताकि कानूनी रूप से शादी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज याकृति आवश्यक हो जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शादी दो लोगों में होती है।

जिसकी पहले शादी हो रखी है और वो बिना तलाक लिए फिर से दूसरी शाद रचा लेता है, तो ऐसे कपल का भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नियम है। हालांकि, मुस्लिम परसनल लोग में ऐसा कोई नियम नहीं है।

भारतीय कानून के मुताबिक, जिसे शादी करनी है उसके दोनों पक्षों की समानत होना जरूरी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और शादी के लिए सहमति नहीं दे सकता, तो ऐसे कपल का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। इसके अधिकारी नजदीकी के रिशेदारों में शादी प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा कपल है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकता। कोई ऐसा व्यक्ति

दुबई जाने के लिए वीजा के लिए ऐसे करे सप्लाई

भारतीयों के लिए दुबई जाने का उत्तम अलग ही होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में भारत से कूल एक करोड़ 19 लाख पर्टनर दुबई गए। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्टनर दुबई की यात्रा घूमने या काम के लिए करते हैं। हालांकि जो पहली बार दुबई जाना चाहते हैं, उनके लिए इस विशेषी गतिशील पहुंचने का लेकर कई सालाह होते हैं, जैसे भारत से दुबई कैसे जा सकते हैं? दुबई का वीजा कैसे और कितने दिन में जिला जाता है?

कहाँ है दुबई

दुबई संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का एक आलोचित शहर है जो कि अरब रीमान के बीच में बसा है। यहां दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बुर्ज खलीफा स्थित है। अगर आप इस शहर द्वारा शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इस लेख में दुबई जाने से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दी जा रही है।

दुबई कैसे जाएं

भारत से दुबई की दूरी लगभग 2500 किमी है। हवाई मार्ग से दुबई पहुंचा जा सकता है। दुबई का उंटरेनेशन एयरपोर्ट बहुत बड़ा और यूरोप का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। कई भारतीय शहरों, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद से दुबई के लिए सीधी उड़ान मिल सकती है।

दुबई का वीजा कैसे मिलता है?

भारतीय पासपोर्ट धारक यात्री को दुबई आने के लिए दुबई वीजा की जरूरत होती है। कई तरह के वीजा होते हैं, जैसे दूरिस्त वीजा, विजिट वीजा, ट्राइज़ वीजा आदि। यात्रा के उद्देश्य और ग्राहक की अवधि के आधार पर वीजा का यात्रन कर सकते हैं। अगर आप दुबई घूमने के लिए आवेदन कर सकते हैं तो दुबई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दुबई दूरिस्त वीजा आमतौर पर सिंगल-एंट्री या मल्टीपल-एंट्री के रूप में उपलब्ध होता है, जो 30 दिन, 60 दिन का हो सकता है।

दुबई का वीजा कितने रुपये में बनता है?

30 दिनों का सिंगल एंट्री वीजा लगभग 6,300 रुपये और मल्टीपल एंट्री वीजा 11 हजार रुपये में मिल सकता है। यहां 60 दिनों का सिंगल एंट्री वीजा लगभग 10,500 रुपये और मल्टीपल एंट्री के लिए 15,800 रुपये लग सकते हैं।

बच्चों के लिए दुबई का वीजा

अगर आप परिवार के साथ दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं तो 18 साल से कम आयु के आवेदक यात्री नावालिम निशुल्क दुबई पर्टनर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बच्चे के साथ वैध पर्यटक वीजा यात्रा वर्षक जरूर होना चाहिए।

वीजा मिलने में कितना वक्त लगता है?

ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने के लिए दुबई वीजा वेलसाइट पर जाकर एक फॉर्म को भरता होता है। आमतौर पर, वीजा दो से चार कार्य दिन मिल जाता है। दुबई का वीजा कितने रुपये में बनता है और दुबई जाने का किराया कितना है?

कहाँ है दुबई

दुबई का उंटरेनेशन एयरपोर्ट बहुत बड़ा और यूरोप का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। कई भारतीय शहरों, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद से दुबई के लिए सीधी उड़ान मिल सकती है।

दुबई का वीजा कैसे मिलता है?

कम से कम 6 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। व्हाइट बैग्रांड के साथ पासपोर्ट साइज़ फोटो यात्रा के लिए दोनों तरफ का प्लाइटिकट कट कट होता है। दुबई वीजा का वैलिडिटी होनी चाहिए।

दुबई वीजा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

दुबई जाने के लिए ई-वीजा आलाई कर रहे हैं तो कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें

कम से कम 6 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। व्हाइट बैग्रांड के साथ पासपोर्ट साइज़ फोटो यात्रा के लिए दोनों तरफ का प्लाइटिकट कट कट होता है। दुबई वीजा का वैलिडिटी होनी चाहिए।

भारत से दुबई के लिए फ्लाइट का किराया

कई एयरलाइंस भारत के विभिन्न महानगरों से दुबई की सीधी उड़ान संचालित करती हैं। भारत से दुबई तक फ्लाइट का किराया लगभग 25,000 रुपये हो सकता है।

दुबई जाने का खर्च कितना है?

भारत से दुबई यात्रा का पूरा खर्च लगभग 50,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है। इसमें राइट ट्रिप की प्लाइटिकट पर कम से कम 25,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। 6,000 से 7,000 रुपये दूरिस्त वीजा, और 1000 रुपये ट्रेवल इश्योरेंस पर लग सकते हैं। इसके अलावा दुबई में घूमने-फिरने और छात्रों की मिलाकर 20 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं।

छह गुण जो साबित करते हैं कि आपका रिश्ता है सबसे बेस्ट



किसी रिश्ते में होना काफी नहीं होता, बल्कि एक प्रत्यक्ष रिश्ता बनाना जरूरी होता है। एक स्वस्थ रिश्ता के बल प्यार और स्नेह तक समीक्षित हो सकता है जो आपकी साझेदारी को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी रिश्ते को बनाना कामयाब बनाता है, यह उस में शामिल लोगों की जरूरतों और उनकी भावाओं पर निर्भर करता है। अक्सर कुछ सुनहरे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आप एक स्वस्थ रिश्ते में लोग अपने साथी की परवाह करते हैं।

स्वस्थ न हो, जितना होना चाहिए। आप संवाद करके और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आकर अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आकर अपने रिश्ते के इस पहलू को बेहतर बना सकते हैं। अपने रिश्ते के इस पहलू को बेहतर बना सकते हैं।

कमिटमेंट कम

